SHRI V. NARAYANASAMY : I am not going into any controversy. Only one sentence. I would like to make a request on the floor of this House that the pilots should withdraw their strike. *(Interruptions)* ,

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is associating. He has sought permission for associating.

SHRI V. NARAYANASAMY : Partially I am associating and partially I am disassociating.

SHRI V. GOPALSAMY : He is dis-associating, not associating.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please, be very brief. I have many names which have been permitted.

SHRI V. NARAYANASAMY : Pilots should immediately withdraw their work-to-rule. That is the slow-going policy that they are adopting the demands that they are making, no Airlines would be able to fulfil.

SHRI V. GOPALSAMY : Their demands are very much justified.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Ram Naresh Yadav. *(Interruptions).* I am not allowing. Nothing will go on record. We ar© not having a discussion on this.

SHRI V. NARAYANASAMY : *

SHRI V. GOPALSAMY : *

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Narayanasamy, are you associating or dis-associating 7

SHRI V. NARAYANASAMY : Both, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You cannot do that. Let me have Mr. Ram Naresh Yadav.

Problems being faced by Farmers in Uttar Pradesh due *to* shortage of Fertilizers mid rise in their Prices

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं एक ऐसे विशेष विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं. (व्यवधान)

उपसभापति : यादव जी, बोलिए ।

श्री राम नरेश यादव : . . . जो किसानों से संबंधित है और विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और उससे संबंधित जो किसानों का प्रश्न है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

वह यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कृत्रिम खाद का अभाव हो गया है और उसके साथ साथ उसके परिणामस्वरूप उसके दाम भी बढ़ गए हैं । परिणाम यह हो रहा है कि रबी की बुआई शुरू है और रबी की बुआई जब शुरू है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में रबी की बुआई के लिए जो अनुमान लगाया गया है, पंद्रह लाख टन की खपत का अनुमान लगाया गया है । लेकिन वह 15 लाख टन की खपत का जो अनुमान है, वह इस समय उपलब्ध नहीं है और वह इसलिए उपलब्ध नहीं है कि पिछले दिनों जो डी –नाइसेंसी– करण हो गया खाद का, तो उसकी वजह से जो वहां के व्यापारी और दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने खाद दबा ली है और परिणाम यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो फंसी है दूसरी जगह पर—उसके लिए तो केवल मंदिर–मस्जिद के अलावा न तो किसान है, न तो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं और जब यह समस्या नहीं है, तो तेरह करोड़ जो प्रदेश का निवासी है, जिसका आधारभूत ढांचा खेती है, उस खेती के लिए आज वह खाद को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है ।

इसके अलावा किसान के गन्ने का जो बकाया है, वह आज भी उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है, जिसके कारण और भी उसके सामने समस्या पैदा हो गई है और जब रामकोला में किसान अपने गन्ने के बकाया पैसे की मांग

*Not recorded.

करने लगे, तो वहां पर गोलियां भी बरसाई गई और लोगों को जेलों में फंसाया गया और लाठियां जिस तरह से बरसाई गई, महोदया, वह बहुत ही वैसी कहानी रही है।

इसलिए इस समय जो स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अगर हमारा उत्पादन नहीं होगा, किसान को यह खाद नहीं मिलेगी, तो किसान कैसे उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए यह जो कमी कृत्रिम दिखाई पड़ रही है, वहां पर प्रदेश में, और प्रदेश की सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही है, हमारा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार इस बात का निर्देश प्रदेश सरकार को दे कि किसानों के लिए इस समय रबी की बुआई के लिए, क्योंकि अगर रबी की बुआई नहीं हो पायेगी, ठीक से नहीं होगी, तो हमारे प्रदेश में रबी का उत्पादन भी कम हो जाएगा और जब रबी का उत्पादन कम हो जाएगा तो खाने की समस्या जो सबके सामने आती है, वह प्रदेश के सामने भी पैदा होगी और देश के सामने पैदा होगी और तब मजबूर होकर के सरकार को कभी बाजार को नियंत्रण करने के लिए आयात करने की दिशा में भी कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं।

इस लिए ऐसी सूरत में प्रदेश की सरकार जो इस समय निकम्मी साबित हो गई है, [illegible] र्देश दिया जाए कि वह जल्दी से [illegible] ो उपलब्ध कराए ताकि किसान [illegible] ठीक से कर सकें और मार्कीट [illegible] लोग हैं, या जो बड़े-बड़े बेचने [illegible] ार हैं, जिनके बल पर प्रदेश में [illegible] आई है, उनके खिलाफ़ कार्यवाही [illegible] उसको मार्कीट में लायें ताकि उससे [illegible]किसान को उपलब्ध करा सकें। घंटी

यह प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर बात है, किसानों के लिए गंभीर बात है और रबी का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्देश आपके माध्यम से, केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से प्रदेश सरकार को जाना चाहिए ताकि प्रदेश सरकार जो सो रही है कहीं दूसरी ना[illegible]म पर, ज[illegible] जाग करके किसानों के हित का ध्यान करे। ...... (व्यवधान)

यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं भी अपने आप को राम नरेश यादव जी से संबद्ध करते हुए इनकी बात का समर्थन करता हूं। मैं इसके साथ ही यह भी मांग करता हूं कि लेवी चीनी का जो पैसा केन्द्र-सरकार ने रखा हुआ है वह पैसा प्रदेश सरकार को दें ताकि गन्ने के बकाये की पेमेंट हो। (व्यवधान) और लेवी चीनी मिलों से उठा लें।

श्री राम नरेश यादव : सरकार को सोचना-समझना चाहिए ताकि जो सांप्रदायिकता फ़ैला कर प्रदेश के किसानों के अंदर जो स्थिति आज पैदा कर दी जा रही है, वह न हो जाए और उनका ध्यान खेत की तरफ़, खलिहान की तरफ़ लगे, उत्पादन की तरफ़ लगे, यही मेरा आपके माध्यम से आग्रह है बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Before I call Mr. Inder Kumar Gujral to make his Special Mention, I would call Mr. Syed Sibtey Razi to take his seat here as he has been appointed by the Chairman as a Vice-Chairman on the panel of Vice-Chairmen. I hope you peopic will cooperate with him in the same manner as you cooperate with me. ..*(Interruptions)*. .. I wish you all success in the Chair.

[The Vice-Chairman (Shri Syed Sibtey Razi) in the Chair]

SHRI V. GOPALSAMY : We at« happy that you have included Mr. Narayanasamy also on the paoel.

श्री सिकन्दर बख्त : आपका स्वागत है, वाईस-चेयरमैन साहब।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra) : I congratulate the Hon. Member for occupying the Chair for the first time. I wish him all success in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Thank you very much. I assure you that I will try my best in my humble way to. run this House. I feel it my privilege to be. here. I hope, as the Deputy Chairman has said, you would try to extend all your co-operation to me from your side. From my side I assure you to do my best.

Thank you very much.

Now I request Mr. Indet Kumar Gujral.

Policies announced by the Minister of Energy to totally follow the World Bank Conditionalities about Tariff, etc.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar) : Sir, I am rising to raise a point of grave national interest regarding the way in which national interest is being flouted.

The hon. Minister of Power. Mr. Kalp Nath Rai, told the World Bank President in his presence in a TV interview which was broadcast in a programme by the Zee TV on Tuesday, that his Department had accepted all the conditionalities of the Bank and that all-out efforts would be made to ensure their impiementation. I quote him now :

> "In the urban sector, you kuow, we are trying to implement all the policies of the World Bank. All the conditionalities you have put, we are accepting. As the Minister of Power I have spoken on this for a long time."

Then he continues :

> "I have said that agriculture tariff must be minimum 50 paise. Cost-based and efficiency-bused power tariff - should be applicable. Now we have accepted the presence of private sector. We have amended the law by amending the electricity law in the Parliament.".

He continues, and again I quote :

> "Private sector participation has been allowed because we are accepting your World Bank's policies."

Very interesting he says that. Significantly, this programme, Sir, was Broadcast twice through the international hook-up. As a continuation of that, the Government has taken a very unusual step. They have done one thing. They have derided that they are going to privatise electricity distribution in Delhi. Tenders have been called. A task force for this purpose has been set up. The names of the members of the task force have been given. They are now examining how they should transfer the distribution work. All this is being done, while this House is not being taken; in confidence. I don't want to use harsh words. But, I think, sometimes one gets a bad impression, where it is liquidation of P.S.U. shares or it is liquidation of the policies. My hon. friend, Mr. Finance Minister, is here. He has all the time been telling us that the conditionalities, all the conditions, all the dictates of the World Bank are not being followed. Here is' a Minister's statement on record, made in the presence of the World Bank President, which has been broadcast twice. Tt.is very interesting. The commentator said that even the President of the World was feeling embarrassed by the way the Minister was trying to tell him, "We for you say. Sir what more do yo do ?"

I don't think that this coun. been more humiliated--! don't t this country has been ever put ii pocket of foreigners—than this stau I would request the hon. Minister—here-to react or call Mr. Kalp Nath k. to tell us what he said, why he said it and why he humiliated this country.

Thank you

SHRl S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, we all associate ourselves with the very important special mention that Gujralji has made. I think the Government should come forward with an